

भौतिक रूप से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ परंतु स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्रता का अर्थ होता है जहाँ अपनी प्रणाली-अपनी व्यवस्था हो या दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ अपना तंत्र (System) हो। आइए इस लेख द्वारा जानें भारत अभी भी किन किन क्षेत्रों में गुलाम है। प्रस्तुत लेख [भाई राजीव दीक्षित जी](#) के एक भाषण का लिखित स्वरूप है जिसमें मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा की गई है। आप इस व्याख्यान को स्वयं भाई राजीव जी के श्रीमुख से नीचे दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं।

[https://docs.google.com/file/d/0B8n\\_36gK-KF4NU12VG8tS2g4Rkk/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/file/d/0B8n_36gK-KF4NU12VG8tS2g4Rkk/edit?usp=sharing)

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली स्वदेशी नहीं है, जिसे आप शायद जानते भी हों। इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता था T. B McCauley। McCauley ने भारत को गुलाम बनाने हेतु जो रणनीति बनाई थी उसका पालन अंग्रेज़ी हुकूमत ने किया। मानव विज्ञान या Anthropology मैकाले का डिज़ाइन किया हुआ वो विषय है जिसमें गुलाम देश के लोगों की मानसिकता का अध्ययन किया जाता है और शोध करके उन्हें गुलाम ही बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहला Convent school मैकाले ने ही खोला था कलकत्ता में जिसके तहत भारतीय दर्शनों को नीचा दिखाने और अंग्रेज़ी मानसिकता को सराहने की व्यवस्था थी क्योंकि मैकाले यह जानता था अगर भारतीयों को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उनकी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था पर चोट पड़नी चाहिए।

एक झूठ जो हमेशा से प्रचारित किया जाता रहा है कि आर्य मध्य एशिया और यूरोप से भारत में पहुँचे जो कि सर्वथा गलत और अवैज्ञानिक बात है। सबसे पहली बात तो इन अंग्रेज़ों को यह समझ में नहीं आई कि आर्य कोई प्रजाति नहीं थी! आर्य शब्द वैदिक साहित्य में उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जो आदर्श होता था तथा जिसका जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय होता था। आर्यत्व का उस व्यक्ति के धर्म, जाति या वर्ण से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे हर संप्रदाय में श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए एक संज्ञा होती है। दूसरा तथ्य यह है कि भारत भूमि भौगोलिक दृष्टि से अबाधित जीवन जीने के लिए धरती पर सबसे उपर्युक्त राष्ट्र है क्योंकि यहाँ न तो अधिक गर्मी है और न ही अधिक सर्दी। यहाँ का वातावरण जीवन यापन तथा जनसंख्या के घनत्व के लिए सबसे उपर्युक्त है। जिस तरह जीवन किसी अन्य ग्रह से धरती पर नहीं आ सकता ठीक उसी प्रकार अन्य देशों से भारत में आकर बसना सर्वथा अवैज्ञानिक, हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात है क्योंकि जीवन वहीं सबसे पहले पनपता जो जगह उसके लिए सबसे अनुकूल हो, फिर वहाँ से वो अन्य जगहों तक पहुँचता है! तीसरा तथ्य यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय DNA conference में यह साबित हो चुका है कि भारत वासियों के DNA तो दुनिया के अन्य लोगों में हैं परंतु उनके DNA भारतवासियों में नहीं हैं।

अंग्रेजों ने दुनिया के सबसे बड़े न्याय शास्त्र 'मनुस्मृति' पर भी आघात किया जिसका कारण यह था कि जिस देश को गुलाम बनाना हो, उस देश के लोगों पर अन्याय करना होता है। यह अन्याय अंग्रेज कानून बना कर करते थे जिसके लिए मनुस्मृति जैसा न्यायशास्त्र एक बाधा था, जिसके आधार पर भारत में करोड़ों वर्षों से न्याय होता चला आ रहा था। William Hunter नाम का एक अंग्रेज था जो संस्कृत जानता था। उसने भारत के शास्त्रों के साथ इतनी छेड़ छाड़ की कि शास्त्रों के वाक्यों का अर्थ बदल कर रख दिया। यह सब एक सोची समझी चाल का नतीजा था जिसका बीज मैकाले ने बोया था। भारत की संस्कृति इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह पलटना अकेले हंटर के बस की बात नहीं थी इसीलिए उसने एक टीम का गठन किया जिसका नाम था William Hunter Commission। इस कमीशन ने अंधा धुंध काम किया और ऐसा syllabus तैयार करके दिया जिससे भारत वासी खुद को हमेशा हीन समझें। आगे चलकर उन्होंने बहुत से झूठ दुनिया में प्रचारित करे जैसे भारत शुरू से गरीब देश रहा है, भारत की जनता के पास कपड़े नहीं थे, भारतवासी गौ माँस खाते थे, भारत शुरू से गुलाम देश रहा है और अब अगर हम इस पर शासन कर रहे हैं तो आपत्ति क्या है, इत्यादि। हमारे देश में लाखों गुरुकुल चलते थे जिन्होंने भारत को 97% साक्षरता प्रदान की। मैकाले के एक कानून Indian Education Act ने सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। इस कानून के तहत उन्होंने संस्कृत पर प्रतिबंध लगा दिया, गुरुकुल जला दिया और गुरुकुल के आचार्यों को पता नहीं कितनी तरह की यातनाएँ देकर मार डाला! वे यहीं तक नहीं रुके; उन्होंने हमारे शहीद क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा और यह कानून जस का तस हमारे देश में अभी तक बदस्तूर जारी है। इस तरह के 34,735 कानून बनाये गए अंग्रेजों द्वारा। आज़ादी के बाद इन सभी कानूनों को रद्द कर देना चाहिए था परंतु आज़ादी के 65 सालों के बाद भी ये सारे कानून अभी तक देशवासियों पर लागू हैं।

1857 की क्रांति में भारत के 350 स्थानों को अंग्रेजों से खाली करा लिया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम में 3,64,000 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इस आन्दोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कानून लागू कर दिया जिस के बल पर अंग्रेजों को ये स्वायत्तता मिल गई कि वे किसी भी भारतीय को बेरोक टोक मार पीट सकते हैं और इस दौरान अगर कोई भारतीय मर जाता है तो मारने वाले अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा! इस कानून को नाम दिया गया Indian Police act, 1860। इस कानून में एक धारा है जिसे कहते हैं Right to offense। इसी के तहत अंग्रेजों को जान से मार देने की स्वतंत्रता मिल गई। बदले में अगर कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारी को मार देता है तो ब्रिटिश सरकार उसे दंड देगी जो उस समय फाँसी होती थी। आपको बताना चाहूँगा कि ये वही कानून है जिसने इस देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जान ली और जिसके कारण अमर शहीद भगत सिंह जी को फाँसी हुई। कहानी यह थी कि Indian Police Act की ही तरह कुछ और कठोर कानून बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक commission का गठन किया और उसे भारत भेजा जिसका नाम था Simon Commission। इस commission का विरोध करने के लिए लाला जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर में एकत्रित हुए और वहाँ प्रदर्शन किया 'GO BACK SIMON' के नारों साथ। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था Saunders उसने कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ बरसाने का आदेश दे दिया। उसने लाला जी के सिर पर लाठी से 14 बार आघात किया जिससे उनकी वहीं मृत्यु

हो गई। भगत सिंह जी ने कोर्ट में Saunders के खिलाफ एक केस दायर किया और कहा कि किसी भी अंग्रेज़ अधिकारी को इस तरह के अमानवीय व्यवहार की इजाजत नहीं होनी चाहिए। परंतु अदालत ने Saunders को Indian Police Act नाम के उस कानून के तहत बा इज्जत बरी कर दिया जिसमें वो किसी भी भारतीय पर अत्याचार कर सकता था! इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने Saunders को गोली मारी। जब भगत सिंह जी ने खुद को पुलिस के हवाले किया था उस समय उनको फाँसी की सजा इसी Saunders को मारने के लिए, Indian Police Act नाम के कानून के तहत मिली। बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के आज़ाद भारत में ये कानून अभी तक कायम है। इसी तरह का लाठी चार्ज अभी तक हमारे देश में होता है। अंधे हों, अपाहिज हों, किसान हों, बहु बेटियाँ हों किसी पर भी पुलिस नेताओं के इशारों पर लाठी चार्ज कर देती है। 4 जून 2011 की वह काली रात इसी कानून का नतीजा थी जब पुलिस ने रामलीला मैदान में सोये हुए लोगों पर लाठियाँ बरसा दी थीं।

एक और अंग्रेज़ अधिकारी आया भारत में जिसका नाम था Dalhousie। इस व्यक्ति ने भारत में कानून लागू करवाया जिसका नाम था Land Acquisition Act, 1848। कानून यह कहता था कि जिस जमीन पर सरकार का नोटिस लग जाएगा वो जमीन सरकार की हो जाएगी और उस जमीन के मालिक को वो जगह खाली करनी पड़ेगी! इस कानून के तहत डलहौज़ी ने 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीनी और उन्हें बेघर कर दिया। आज आप अपने शहर में जिन लोगों को फुटपाथ पर जीवन बसर करते हुए देख रहे हैं या वे लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग वे हैं जिनके पूर्वज इसी कानून का शिकार हुए थे! आज भी यह कानून जस का तस इस देश में कायम है। कभी भी कहीं भी सरकार का बोर्ड लग सकता है और कुछ दिनों के नोटिस पर आपको जगह खाली करनी पड़ती है। ये कानून हमारी सरकार को इतना भाया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्थान का नाम इस अधिकारी की याद में ही रख दिया! उस जगह का नाम भी Dalhousie है और आप में से कई लोग वहाँ गए भी होंगे।

1857 की क्रांति में लगभग 3,64,000 अंग्रेज़ मारे गए। एक अंग्रेज़ी सर्वेक्षण के अनुसार पता चला कि भारत वासी बहुत बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करते हैं। उस सर्वेक्षण में पता चला कि यह धनराशि थी 480 करोड़। यह धनराशि उस समय के रूपए के मूल्य के बराबर है।

आज का रूपया उस ज़माने के रूपए का 300 गुना हो चुका है यानि कि उस ज़माने का 1 रूपया के ज़माने के 300 रुपये के बराबर है। इसका सीधा सा अर्थ था कि भारतवासियों के पास संचित धन बहुत था और जब तक ये संचित धन भारतवासियों के पास रहता तब तक अंग्रेज़ इसी तरह मारे जाते। इसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को लूटने का कानून बनाया जिसका नाम था Indian income tax act | इस कानून के तहत भारतीयों पर 97% कर लागू कर दिया गया। जितना भी भारत वासी कमाते थे उसका 97% कर भुगतान अंग्रेज़ी सरकार को करना पड़ता था। जो लोग कर नहीं दे पाते थे उन्हें कील लगे कोड़ों से 100 बार पीटा जाता था! कुछ किसान तो 20-30 कोड़ों तक अपने प्राण दे देते थे फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहु बेटियाँ से दुर्व्यवहार किया जाता

था। आज़ादी के बाद इस कानून को बिलकुल खत्म कर देना चाहिए था परंतु अभी तक यह कानून देश पर लागू है बस कर की दर 97% से कम करके 30% कर दी गई है।

एक और कानून है जिसकी आड़ में हमारे देश की भूसम्पदाएं दिनों दिन लुट रही हैं और न जाने कितने आदिवासी भूमिहीन हो रहे हैं। यह वो कानून है जो देश सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं में से एक 'नक्सलवाद' का जन्मदाता है। इस कानून का नाम है Indian Forest Act | पुराने ज़माने में ग्रामीण लोग खाना पकाने और मुख्य रूप से ईंधन के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर थे। तब गैस वाला चूल्हा नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने इस कानून के तहत जंगल से लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया और तर्क दिया कि इस तरह से एक दिन सारे जंगल साफ़ हो जायेंगे इसीलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है कि भारतवासियों को लकड़ियाँ काटने से रोका जाए। इस तरह जो व्यक्ति लकड़ी काटता हुआ पकड़ा जाता, उसे सज़ा मिलती। इस कानून के बाद जंगल और उसमें दबी भू संपदाएं सीधे तौर पर अंग्रेजों के कब्ज़े में आ गईं। उन्होंने एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया जंगल के पेड़ काटने के लिए क्योंकि उन पेड़ों का इस्तेमाल सिगरेट के कागज़ के लिए होता था। धूम्रपान से मौतें अलग और जंगलों का काटना अलग! आँकड़े बताते हैं कि इस हरकत ने भारत के 77% वनों को तबाह कर दिया। यही नहीं अब तो विदेशी कंपनियों के दबाव में सरकार जंगल के जंगल इस कानून के तहत साफ़ करा देती है और लाखों वनवासियों को बेघर कर देती है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो यही वनवासी न चाहते हुए भी बाघी बनने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें ये सरकार नक्सलवादियों के नाम से संबोधित करती है। यही लोग जो देश की धरोहर बनकर समाज को सशक्त कर सकते थे, गलत नीतियों और कानूनों के शिकार होकर हिंसा का मार्ग अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं।

अंग्रेज़ जब इन्हीं परिवारों की बहू बेटियों का शीलहरण करते थे तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता था। जब लोग अंग्रेज़ अधिकारियों के पास शिकायतें लेकर पहुँचते थे तो उनके सामने प्रश्न खड़ा हो जाता था कि न्याय दें या अपने साथियों को बचाएँ? इसके समाधान के तौर पर फिर एक कानून बना कि बलात्कार की शिकार महिला को यह पहले साबित करना पड़ेगा कि उसका शीलहरण हुआ था! जब तक वो साबित नहीं कर देती तब तक आरोपित अंग्रेज़ अधिकारी को कोई सज़ा नहीं मिल सकती। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का भद्दा मजाक था यह न्याय के नाम पर!! इसके बाद तो देश में बलात्कारों की बाढ़ सी आ गई। सिर्फ 1-2% मामलों में अंग्रेज़ अधिकारी दोषी पाए जाते थे क्योंकि कुछ ही महिलाएं साहस दिखा पाती थीं। एक अत्यंत अधम और बेशर्म अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम था Col. Wheel, ने अपनी डायरी में लिखा है कि, “मुझे ज्ञात नहीं वो दिन जब भारत में अपने प्रवास के दौरान मैंने किसी महिला को अपनी हवस का शिकार न बनाया हो।” इसी के नाम पर भारत सरकार ने सम्मान स्वरूप Wheel book stall भारत के लगभग हर रेलवे स्टेशन पर खोल रखे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसे आज हम आज़ादी समझ रहे हैं वो मात्र एक भ्रम ही नहीं एक बहुत बड़ी शर्म और अपमान है हमारे लिए!

यही बलात्कार की पीड़ित महिलाएं, अपने साथ हुए दुराचार के बाद परिवार और समाज से बहिष्कृत कर दी जाती थीं। फिर इनके सामने दो ही विकल्प रह जाते थे या तो आत्महत्या या फिर दुराचारियों के पास शरण! इन अंग्रेजों ने ऐसी पीड़ित महिलाओं से नित्य दुराचार के लिए एक तरकीब निकाली और इन्हें रहने के लिए एक अलग से स्थान दिया जहाँ सभ्य व्यक्ति नहीं जाया करते, जिसे हम वेश्यालय कहते हैं। भारत का सबसे पहला वेश्यालय पश्चिम बंगाल के सोनागाछी स्थान पर अंग्रेजों ने खोला। कुछ समय बाद जब वहाँ पीड़ित महिलाओं की तादाद बढ़ने लगी तो इस जगह को ब्रिटिश सरकार ने licence दे दिया ताकि यहाँ खुलेआम अभद्रता का नंगा नाच हो सके! बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दुष्कर्म और अमानवीय व्यवहार की काली याद अभी तक हमारे देश में मौजूद है। और आज इस स्थान जैसे कई स्थान भारत के लगभग हर जिले और तहसील में चलाये जा रहे हैं। प्रशासन को ये इलाके भी पता होते हैं पर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। आज यह दुष्कर्म एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गया है जिसमें प्रतिवर्ष न जाने कितनी माताएं और बहनें धकेली जाती हैं!

वर्तमान भारतीय कानून व्यवस्था के तीन स्तंभ हैं - IPC (Indian Penal Code), CPC (Civil Prodeure Code) तथा CRPC (Criminal Procedure Code) | यह ढांचा भारतीय संस्कृति को ध्वस्त कर देने के मंसूबों वाले मैकाले की अगुवाई में बना था। इस कानून व्यवस्था के बारे में Mc Caulay अपने पिता को एक पत्र में लिखता है क, “मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि भारतवासियों को अगले हज़ारों वर्षों तक न्याय नहीं मिल सकेगा।” अंग्रेजों ने एक और देश को गुलाम बनाया जिसका नाम था Ireland | इस देश को चलाने के लिए उन्होंने जो कानूनी दस्तावेज बनाया उसके भी यही तीन अंग थे। अगर आप भारतीय कानून व्यवस्था और Irish कानून व्यवस्था के दस्तावेजों को सामने रखें तो उनमें एक fullstop का भी अंतर आपको नहीं मिलेगा! बस जहाँ Ireland लिखा हुआ है उसे बदल कर India लिख दिया गया है। यह कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि एक जुर्म को साबित करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। यही वजह है कि भारत की अदालतों में 3.5 करोड़ केस लटके हुए हैं! इन केसों में फैसला होता है पर न्याय नहीं दिया जाता क्योंकि यह व्यवस्था न्याय देने के लिए बनी ही नहीं है! अब आप ही बताएं जिस देश को गुलाम बनाना हो उसे न्याय क्यों दिया जाएगा? अन्याय और पक्षपात की नींव पर ही गुलामी की ईमारत खड़ी की जाती है और इतिहास इस बात का गवाह है। यह कानून व्यवस्था हम अभी तक ओढ़े हुए हैं!

---

काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के महाअभियान भारत स्वाभिमान से जुड़े - स्वामी रामदेव

Join movement against corruption and black money bharat swabhiman - swami  
ramdev

---